दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

## आवश्यक सूचना

**आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।**

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 02 नवंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 37

## महत्वपूर्ण एवं खास

### पुरोहितों के विरोध के चलते त्रिवेन्द्र नहीं कर सके केदारनाथ के दर्शन

**रूद्रप्रयाग (आरएनएस)।** श्री केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध किया। भारी विरोध के कारण वे दर्शन नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र बिना दर्शन के ही वापस लौट गए। जबकि भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विरोध के बीच दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में मंगलवार को दर्शन को पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का तीर्थ पुरोहितों ने करीब दो घंटे विरोध किया। काले झंडे दिखाए गए। चारधामों में यात्रा व्यवस्था और प्रबंधन के लिए सरकार की ओर से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, जिसका शुरुआत से ही तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर महापंचायत ने लंबा आंदोलन भी किया था। अब एक बार फिर तीर्थ पुरोहित मुखर हो गए हैं। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के केदारनाथ पहुंचने पर विरोध किया। उनका कहना है कि त्रिवेंद्र रावत ही देवस्थानम को लाने वाले हैं।

### बदरी नाथ धाम मे जमकर हुआ हिमपात

**चमोली (आरएनएस)।** बदरीनाथ धाम में सोमवार दोपहर बाद जमकर बर्फबारी हुई। नीलकंठ, नर नारायण पर्वत सहित बदरी पुरी में बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। बदरीनाथ धाम में आए श्रद्धालुओं बर्फबारी का लुत्फ उठाया। कई श्रद्धालुओं ने तो पहली बार बर्फबारी देखी। इससे वो लोग काफी खुश नजर आए।

### चीन की अब खैर नहीं , नौसेना को मिला शक्तिशाली आईएनएस विशाखापट्टनम

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** दूश्मन देशों के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। सागरीय सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना को एक और घातक युद्धपोत मिल गया है। नौसेना ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई के मझगांव डॉक पर तैयार हुआ पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत पी15बी विशाखापट्टनम 28 अक्टूबर को भारतीय नौसना को सौंपा गया। नौसेना के अनुसार यह जंगी पोत अब नवंबर के अंत तक पूरी तरह से नौसेना में शामिल हो जाएगा। अत्याधुनिक घातक हथियारों से लैस विशाखापत्तनम का पिछले एक वर्ष से ट्रायल चल रहा है। गहरे सागर समेत सभी हथियारों के टेस्ट में यह युद्धपोत खरा उतरा है। जल्द ही नौसना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना के प्रॉजेक्ट 15बी के तहत विशाखापत्तनम का निर्माण किया गया है। 2015 के करीब पहले बार इसी पानी में उतारा गया था। अत्याधुनिक तकनीक एंव घातक हथियारों से लैश युद्धपोत में 312 कर्मियों की रहने की व्यवस्था की गई है। मझगांव डॉक में बने विशाखापत्तनम का डिजाइन नौसेना के डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया है। जहाज के निर्माण के इस्तेमाल हुए कठोर स्टील का निर्माण देश में ही किया है, जबकि इससे पहले युद्धपोत में लगने वाले स्टील के लिए भारत को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। 164 मीटर लंबाई वाले युद्धपोत पर सभी उपकरण और हथियारों की तैनाती के बाद कुल वजन 7,500 टन हो गया है।

### हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नए सुधार एवं सुविधाओं के साथ हज 2022 की घोषणा के साथ ही सोमवार से हज 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है। नकवी ने सोमवार को हज 2022 की घोषणा करते हुए कहा कि सम्पूर्ण हज प्रक्रिया 100 प्रतिशत डिजिटल/ऑनलाइन होगी। हज 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 रखी गई है। हज के लिए आवेदन, ऑनलाइन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हज मोबाइल ऐप के जरिए भी किए जा सकेंगे।

# भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने समझौते पर किए हस्ताक्षर

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** भारत सरकार,मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने 28 अक्टूबर, 2021 को मेघालय राज्य के लिए 40 मिलियन डॉलरकी स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और कोविड-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करेगी।

मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं और इसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएगी,राज्य के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के डिजाइन और कवरेज का विस्तार करेगी,प्रमाणन और बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगीऔर दवाओं तथा निदान के लिए कुशल पहुंच सुनिश्चित करेगी।

इस परियोजना से राज्य के सभी 11 जिले लाभान्वित होंगे। यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी योजना और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करके और उनके नैदानिक कौशल का निर्माण करके लाभान्वित करेगी। यह परियोजना महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभागके अनुसार,स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत और विस्तारित करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। यह परियोजना राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और गुणवत्ता में वृद्धि करेगी। यह स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज का विस्तार करने और इसे राज्य में गरीबों और कमजोर लोगों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने में भी मदद करेगी।

भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा, मेघालय सरकार की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव रामकुमार एस.और विश्व बैंक की ओर सेभारतमें कंट्री डायरेक्टरजुनैद अहमद नेसमझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना मेघालय के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने में मदद करेगी, जिसे मेघा स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएचआईएस) के रूप में जाना जाता है- जो वर्तमान में 56 प्रतिशत परिवारों को कवर करती है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में विलय के साथ, एमएचआईएस अब एक अधिक व्यापक पैकेज पेश करने और शत-प्रतिशत परिवारों को कवर करने की योजना बना रहा है। यह अस्पताल सेवाओं तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को कम करेगी और गरीब परिवारों के लिए भयावह खर्च को रोकेगी।

एक प्रमुख रणनीति के रूप में यहपरियोजना एक निष्पादन-आधारित वित्तपोषण प्रणाली की ओर बढ़ेगी, जहां डीओएचएफडब्ल्यू और उसकी सहायक कंपनियों के बीच आंतरिक निष्पादन समझौते (आईपीए) से सभी स्तरों पर अधिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा। इससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रणाली के प्रबंधन में सुधार लाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और राज्य बीमा एजेंसी की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

# यूपी के बाइक बोट घोटाले में सीबीआई ने दर्ज किया केस

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की कंपनी बाइक बोट की ओर से किए गए 15,000 करोड़ रुपये के बड़े घोटाले के मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी और 14 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने देश भर में लाखों लोगों से ठगी की है। इस कंपनी के नाम पर लोगों को बाइक टैक्सी में निवेश का ऑफर दिया गया था। इसके तहत 15,000 करोड़ रुपये की ठगी की गई और फिर चंपत हो गए। यह घोटाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की ओर से किए गए फ्रॉड से भी बड़ा माना जा रहा है।

संजय भाटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई थी। इसके बाद बाइक बोट नाम से स्कीम की शुरुआत की गई। इसके तहत संजय भाटी और उसके साथियों ने निवेशकों को 1,3,5 या फिर 7 बाइकों में निवेश के बाद आकर्षक रिटर्न का ऑफर दिया गया। यह कहा गया कि यह बाइक टैक्सी स्कीम है और इसमें पैसे लगाने पर लोगों को बड़ा रिटर्न मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हजारों करोड़ की ठगी करने के बाद संजय भाटी और उसके साथी चंपत हो गए। कहा जा रहा है कि संजय भाटी फिलहाल देश में ही नहीं है।

**सीबीआई की एफआईआर में पुलिस पर भी उठा सवाल-** सीबीआई से पहले इस केस में ईडी ने जांच शुरू की थी। एजेंसी की ओर से कंपनी के प्रमोटरों की 216 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 2 लाख लोगों से ठगी का यह मामला है। इसके तहत कंपनी ने विज्ञापन जारी करके लोगों से स्कीम में निवेश की अपील की थी। इसके अलावा सीबीआई ने अपनी एजेंसी में पुलिस की ढिलाई पर भी सवाल उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी और एसपी क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपनी शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया था।

# दिल्ली में बेकाबू हुआ डेंगू, अब तक सामने आए 1530 से अधिक केस

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** राजधानी दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बेकाबू होता जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी वीकली रिपोर्ट के अनुसार, तीनों निगमों में अब तक डेंगू से मरने वालों लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है और डेंगू के 1537 मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से गंभीर होते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया है और दिल्ली में बढ़ते डेंगू के मामलों की निगरानी के लिए एक एक्सपर्ट टीम का गठन करेगा।

दिल्ली में डेंगू की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को बुलाई गई एक हाईलेवल मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय समन्वय पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डेंगू के हॉटस्पॉट की पहचान, फॉगिंग और समय पर इलाज जैसी जमीनी पहल की जानी चाहिए। केंद्र डेंगू के बढ़ते मामलों वाले राज्यों में विशेषज्ञों की एक टीम भी भेज रहा है। टेस्ट में तेजी लाने की जरूरत पर जोर देते हुए मांडविया ने कहा कि कई गरीब लोगों का ठीक से इलाज नहीं किया जाता है और उनकी मौत की सूचना भी नहीं दी जाती है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में देशभर में डेंगू की स्थिति पर राजधानी में चल रही समीक्षा बैठक में स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली में वेक्टर जनित बीमारी के लिए गति परीक्षण भी किया जाएगा।

# बंगाल में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दरकिनार

» सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला खारिज

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगाधत्री पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल के पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन पटाखों के उपयोग को विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया है जिनमें प्रदूषणकारी सामग्री का उपयोग होता है। पीठ ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

पीठ ने टिप्पणी की, अलग-अलग तरह के लोग हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध हो। हमें बेरियम साल्ट जैसे प्रतिबंधित पदार्थ के उपयोग के खिलाफ तंत्र को मजबूत करना होगा। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018, जुलाई और अक्टूबर 2021 के आदेश में हरे पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देते हुए पटाखों में बेरियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आधार पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कि कार्यपालिका के लिए उल्लंघन करने वालों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा क्योंकि हरित पटाखों को अलग करने के लिए कोई तंत्र नहीं है और कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के लिए असंभव कार्य है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है और पश्चिम बंगाल अपवाद नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने कहा, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश पारित कर चुका है। इसे समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

# रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान दिया

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी ने प्रसार भारती के समारोह के हिस्से के रूप में आकाशवाणी का प्रतिष्ठित सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए।

भारत के महान इतिहास का स्मरण करते हुए और मौर्य साम्राज्य के तत्वावधान में जटिल रूप से जुड़े छोटे राज्यों के संघ के रूप में भारत की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए, जनरल बिपिन रावत ने बताया कि हमारा राष्ट्र अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं, 200 से अधिक बोलियों, एक दर्जन जातीय समूहों, कई संप्रदायों और उप-संप्रदायों वाले सात धार्मिक समुदायों तथा 68 सामाजिक-सांस्कृतिक उप-क्षेत्रों, कई संस्कृतियों का एक आकर्षक और जटिल सम्मिश्रण है। उन्होंने एक ऐसे भारतीय राष्ट्र की परिकल्पना में सरदार पटेल की भूमिका पर जोर दिया जो विविधता में एकजुट है, एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरने के लिए समर्पित और संकल्पित है और अपनी आंतरिक शक्ति से किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है।

सरदार पटेल के मिशन और 565 रियासतों को एक संप्रभु भारत में एकीकृत करने के कठिन कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए जनरल रावत ने कहा कि सुरक्षा, न्याय, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक राजनीति को राष्ट्र निर्माण के स्तंभों के रूप में माना जा सकता है। जनरल रावत ने चाणक्य के युग से प्रचलित रणनीति को विवेकपूर्ण ढंग से लागू करते हुए रियासतों के साथ आम सहमति बनाने में सरदार पटेल के अथक प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।

जनरल रावत ने कहा कि भगवद् गीता के अनुसार, जो कहती है, अपना कर्तव्य मानते हुए, आपको उसका त्याग नहीं करना चाहिए, भारतीय सैन्य अकादमी के सभी कैडेट, अपने प्रशिक्षण के समापन से पहले, सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, जो इस बात पर जोर देती है कि राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सर्वोपरि है, उसके बाद कमान के तहत लोगों का सम्मान, कल्याण और आराम का स्थान है, जबकि व्यक्तिगत सुख, आराम और सुरक्षा का स्थान हमेशा सबसे अंतिम होता है।

# भारतीय कोरोना टीके कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने दी मंजूरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** भारत में बने कोरोना टीके को भले ही अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे अप्रूव्ड टीकों की सूची में शामिल किया है। भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने यात्रियों के वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए मंजूर कर लिया है।

सोमवार को यहां ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल ने यह जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार की ओर से कोवैक्सीन को यह ग्रीन सिग्नल ऐसे वक्त में मिला है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी के लिए देसी टीके को कई सप्ताह से इंतजार है। इस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ और जानकारी की मांग की है। अब डब्ल्यूएचओ की होने वाली बैठक में भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। इसी साल 19 अप्रैल को ही भारत बायोटेक की ओर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के समक्ष आवेदन किया गया था। इस टीके को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया था।

# मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ने रफ्तार पकड़ी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज एनएचएसआरसीएल के मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए गुजरात के नवसारी कास्टिंग यार्ड में 40 मीटर स्पैन के एक और फुल स्पैन प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (क्रास्ट) बॉक्स गर्डर की कास्टिंग का शुभारभ किया ढ्ढ पिछले महीने, 28 अक्टूबर को गुजरात के आणंद में कास्टिंग यार्ड में पहले फुल स्पैन गर्डर की कास्टिंग की गई थी।

इस अवसर पर श्रीमती दर्शना जरदोश ने एनएचएसआरसीएल व एल×टी को बधाई देते हुए कहाँ, जब देश कोरोना से झूझ रहा था तब भी एनएचएसआरसीएल और एल×टी ने कोरोना सम्बंधित सुरक्षा अपनाते हुए ज़ोर शोर से काम जारी रखा तथा इस प्रोजेक्ट को आज इस मुकाम तक पहुंचाया ढ्ढ उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और जल्दी ही यह इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा ढ्ढ

40 मीटर स्पैन का पीएससी बॉक्स गर्डर का वजन लगभग 970 मीट्रिक टन है, जो भारत के निर्माण उद्योग में सबसे भारी पीएससी बॉक्स गर्डर होगा। 40 मीटर स्पैन गर्डर को सिंगल पीस के रूप में कास्ट किया जा रहा है यानी बिना किसी निर्माण जोड़ के, जिसमें 390 घन मीटर कंक्रीट और 42 मीट्रिक टन स्टील शामिल है।

वायडक्ट के निर्माण में तेजी लाने के लिए, सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण समानांतर में किया गया है। सबस्ट्रक्चर यानी पाइल, पाइल कैप, पियर और पियर कैप का काम प्रगति पर है, सुपरस्ट्रक्चर के लिए, फुल स्पैन गर्डर्स और सेगमेंटल गर्डर्स को कास्ट करने के लिए सरेखण के साथ कास्टिंग यार्ड विकसित किया गया है ताकि उन्हें कास्ट पियर कैप्स पर भारी मशीनियों का उपयोग करके लॉन्च किया जा सके।

सुपरस्ट्रक्चर के लिए अधिकांश गर्डर 30,35 और 40 मीटर लंबे पूरे स्पैन के होंगे, हालांकि, उन स्थानों के लिए जहां साइट की कमी है, प्रीकास्ट सेगमेंट के सेगमेंटल लॉन्चिंग का उपयोग किया जाएगा। सेगमेंटल गर्डर की तुलना में फुल स्पैन गर्डर को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग प्रगति सेगमेंटल गर्डर लॉन्चिंग की तुलना में सात गुना तेज होती है।

गर्डरों की कास्टिंग के लिए सरेखण के साथ-साथ 23 कास्टिंग यार्ड विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक कास्टिंग यार्ड आवश्यकता के अनुसार 16 से 93 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और हाई-स्पीड रेल एलाइनमेंट के निकट स्थित है। गुणवत्ता के साथ गर्डरों की शीघ्र कास्टिंग के लिए, प्रत्येक कास्टिंग यार्ड में रिबर केज बनाने के लिए जिग्स, हाइड्रोलिक रूप से संचालित प्री-फैब्रिकेटेड मोल्ड्स के साथ कास्टिंग बेड, बैचिंग प्लांट, एग्रीगेट स्टैकिंग एरिया, सीमेंट साइलो, गुणवत्ता प्रयोगशाला और वर्कमैन कैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं।